



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 258]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय - रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अमोनियम नाइट्रेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

संख्या 14/1/2016-डीजीएडी.—यतः मैं. दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड और स्मार्टकेम टैक्रॉलाजी लिमिटेड (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है जिसमें रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से "अमोनियम नाइट्रेट" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के रासायनिक यौगिक "अमोनियम नाइट्रेट" है जिसका रासायनिक सूत्र एनएच₄एनओ₃ है। इसमें नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया का साल्ट होता है। नाइट्रोजन की मात्रा ठोस रूप में भार के 28 प्रतिशत से अधिक होती है। कमरे के तापमान पर, अमोनियम नाइट्रेट, एक सफेद क्रिस्टलीय रंगहीन रूप में दिखाई देता है। इसका गलनांक 169.96 डिग्री सेल्सियस या 337.3 डिग्री फारनहाइट है।

4. अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल से विभिन्न रूपों जैसे मैल्ट, प्रिल्स, फ्लेक्स, ग्रेन्युल्स, लम्पस आदि में उत्पादित किया जाता है। संबद्ध वस्तु अमोनियम नाइट्रेट ठोस रूप में है जिसका घनत्व 0.83 जी/सीसी से अधिक हो। संबद्ध वस्तु में अमोनियम नाइट्रेट शामिल है चाहें प्रिल, दानेदार या अन्य ठोस रूप में हो अभिवर्धकों या कोटिंग के बिना या सहित और 0.83 जी/सीसी से अधिक के बल्क घनत्व वाला हो। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशेष रूप से 0.83 जी/सीसी के बराबर या उससे कम बल्क घनत्व वाले ठोस अमोनियम नाइट्रेट या मैल्ट या कम घनत्व वाले अमोनियम नाइट्रेट को बाहर रखा गया है।

5. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 31 के उप-शीर्ष 3102 30 00 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुरोध के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह याचिका मैं, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड और स्मार्टकेम टैक्रॉलाजी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है। याचिकाकर्ता ने एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक/आयातक से संबद्ध हैं। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

शामिल देश

8. वर्तमान जाँच रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का दावा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1)(ग) के अनुसार परिकलित सामान्य मूल्य का आधार पर किया है। याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य का दावा किया है।

निर्यात कीमत

10. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को आईबीआईएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए निर्यातक देश में समुद्री भाड़े, अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन के लिए कीमत संबंधी समायोजन किये गए हैं।

पाटन मार्जिन

11. संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो दर्शाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है और अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना का आकलन किया गया है। याचिकाकर्ता ने समग्र रूप से और उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, बाजार हिस्से, नियोजित पूंजी पर आय, लाभप्रदता में गिरावट के अनुसार परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच अवधि (पीओआई)

13. याचिकाकर्ता ने वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 (12 महीनों) तक रखने का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 (12 महीने) को पीओआई के रूप में निर्धारित किया गया है ताकि बिल्कुल हाल के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। तथापि, क्षति जाँच अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 12 से मार्च 13, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015 और जांच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

समय-सीमा

15. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। ज्ञात निर्यातक और आयातक जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, को तथापि उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से 40 (चालीस) दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग की याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

18. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

19. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

New Delhi, the 5th August, 2016

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Ammonium Nitrate” originating in or exported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran.

F. No.14/1/2016- DGAD.—Whereas Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited and Smartchem Technologies Limited (hereinafter also referred to as ‘petitioner’) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Ammonium Nitrate” (hereinafter also referred to as the subject goods) from Russia, Indonesia, Georgia and Iran (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists justifying initiation of anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry

Product under consideration

3. The product under consideration in the present petition is “Ammonium nitrate”, a chemical compound with the formula NH_4NO_3 . It is composed of nitric acid and salt of ammonia. The nitrogen content exceeds 28% of weight in solid form. In room temperature, ammonium nitrate appears in a white crystalline colourless form. Its melting point is 169.6 degrees Celsius or 337.3 degrees Fahrenheit.

4. Ammonium nitrate is produced from ammonia and nitric acid, in various forms, such as melt, prills, flakes, granules, lumps, etc. The subject goods, are ammonium nitrate in solid form having density above 0.83 g/cc. The subject goods include ammonium nitrate, whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc. Specifically excluded from the scope of product under consideration, is solid ammonium nitrate, having bulk density equal to or below 0.83 g/cc or melt or low density ammonium nitrate.

5. Subject goods are classified under chapter 31 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 3102 30 00. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Like Article

6. The petitioner has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the petitioner, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The petitioner has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the petitioner in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

7. The petition has been jointly filed by Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited and Smartchem Technologies Limited. As per information available in the petition, the production of the petitioner accounts for 100% of the total Indian production. The petitioner has also furnished a declaration stating that they have neither imported the subject goods from the subject country during the POI, nor are

related to any exporter/importer of the subject goods from the subject country. The Authority, therefore, determines that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Countries Involved

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Russia, Indonesia, Georgia and Iran (referred to as 'Subject Countries').

Normal Value

9. The petitioner has claimed normal value of the product under consideration in subject countries on the basis of the constructed normal value in accordance with section 9A (1)(C), Customs Tariff Act, 1975. The petitioner has claimed normal value on the basis of cost of production in subject countries, duly adjusted, including selling, general & administration expenses and reasonable profit.

Export Price

10. Export price of the subject goods from the subject country has been determined by considering transaction wise import data collected from the IBIS. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, marine insurance, port expenses in the exporting country to arrive at ex-factory export price.

Dumping Margin

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating that the subject goods are being dumped by exporters from subject countries into the Indian market and the dumping margin is estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

12. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in market share, return on capital employed, profitability etc. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

13. The petitioner has proposed the period of investigation(POI) for the present investigation from 1st January, 2015 to 31st December 2015 (12 months). However, authority has determined the POI as 1st April, 2015 to 31th March 2016 (12 months) so as to undertake analysis on the most recent data. However, the injury investigation period will cover the data of the previous three years, i.e. April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the POI

Submission of Information

14. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.**

Time Limit

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the

information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's petition within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

Inspection of public file

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority